Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-17, अंक-02 16-31 जनवरी, 2022 (पाक्षिक) ₹20

प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी

'उत्तर प्रदेश में सुशासन और ईमानदार सरकार है'

पीएम-किसान की 10वीं किस्त जारी

पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़

भारत स्टार्ट-अप में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हब बना

बदायूं (उत्तर प्रदेश) में जन विश्वास यात्रा रैली को संबोधित करते
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

बस्ती (उत्तर प्रदेश) में जन विश्वास यात्रा रैली को संबोधित करते
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश
पदाधिकारी बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

बरेली (उत्तर प्रदेश) में एक रोड शो के दौरान
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

हरदोई (उत्तर प्रदेश) में एक जनसभा को संबोधित करते
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के
उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 सपा ने उत्तर प्रदेश में कुशासन दिया, हमने सुशासन दिया : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर (हापुड़) और बदायूं में जन-विश्वास यात्रा के तहत आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और डबल इंजन सरकार...

09 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़

5 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंजाब यात्रा पर थे। उन्हें विकास परियोजनाओं...

12 'देश के किसान का आत्मविश्वास देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य है'

जमीनी स्तर के किसानों को सशक्त बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप प्रधानमंत्री...

14 मणिपुर में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 दिसंबर...

26 प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना...

वैचारिकी
सिद्धांत और नीतियां / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 22

श्रद्धांजलि
स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भाजपा नेता
के. अय्यप्पन पिल्लई का 107 की आयु में स्वर्गवास 24
देवदत्त बरकाताकी नहीं रहे 24

लेख
'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' मेहनती किसानों के
आर्थिक हितों की रक्षा करती है / **विकास आनन्द** 30
उजाला योजना: आवश्यक बदलावों की ओर एक कदम / **विपुल शर्मा** 31

अन्य
हम उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने
की ओर बढ़ रहे हैं: अमित शाह 16
लोकतंत्र की हत्यारी है केसीआर सरकार 18
10 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा 19
देश में 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों का
कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू 20
दिसंबर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये रहा 21
12,031 करोड़ रुपये की हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II को मिली मंजूरी 22
उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य, इस दशक को
उत्तराखंड का दशक बनाएगा: नरेन्द्र मोदी 28
भारतीय इतिहास में मेरठ संस्कृति और शक्ति का
एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है: नरेन्द्र मोदी 29
मन की बात 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दे और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है।

जगत प्रकाश नड्डा

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है तो समृद्धि है, प्रगति है, युवाओं में आत्मविश्वास है, महिला सशक्तिकरण है, किसान भाइयों का सम्मान है, जन-जन में उत्साह है। जनता यहां फिर से कमल का बटन दबाने को लालायित है।

अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वीर बाल दिवस' मनाने के निर्णय से चार साहिबजादों की राष्ट्रभक्ति से न सिर्फ आज करोड़ों बच्चे प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा में अपना योगदान दे पाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उनका बलिदान याद किया जाएगा। इसके लिए मोदीजी का अभिनंदन करता हूं।

राजनाथ सिंह

साल 2014 के बाद कांग्रेस पहाड़ों में दुबक गई थी। उत्तराखंड वासियों को यह तय करना होगा कि हमें 'एक बार इसको, एक बार उसको' की सोच से बाहर निकलना होगा। इस बार कांग्रेस को पहाड़ों से भी बाहर कर दीजिए और भाजपा को पुनः मौक़ा ज़रूर दीजिए।

बी.एल. संतोष

पंजाब से कर्नाटक तक कांग्रेस पार्टी और उसके नेता एक फ्रिंज समूह का हिस्सा बन रहे हैं.... साजिश रच रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, कोविड मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं, कट्टरपंथी ताकतों के साथ हैं.... यह लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं... इनको सफलता नहीं मिल रही है... अब यह पारिस्थितिकी तंत्र बिखर रहा है...

नितिन गडकरी

प्रभु श्रीराम वनवास के लिए अयोध्या से चित्रकूट जिस मार्ग से गए, उसे बनाया जा रहा है। 5 हजार करोड़ रुपए की लागत से 251 किमी लंबाई के रामवनगमन मार्ग में 102 किमी मार्ग का निर्माण पूर्ण हो गया है। 156 किमी मार्ग निर्माण का भूमिपूजन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस मार्ग में श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा पर 2 किमी का 6-लेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़

संपादकीय

पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा को खतरे में डाला गया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है। ध्यान देने योग्य है कि यह घटना तब घटी, जब प्रधानमंत्री हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे थे। प्रधानमंत्री का काफिला लगभग 20 मिनटों तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा तथा सुरक्षा पर संभावित खतरे को देखते हुए वापस लौटने का जिस प्रकार से निर्णय लिया गया, उससे राजनीति के दिन-प्रतिदिन गिरते हुए स्तर पर कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। ये प्रश्न देश की संस्थागत व्यवस्थाओं की शुचिता-निष्पक्षता से भी संबंधित है जो इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण राजनीति पर अंकुश रखता है। क्या विद्वेषपूर्ण राजनीति के लिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? इस घटना से देश की संघीय व्यवस्था, राजनैतिक शुचिता तथा बहुदलीय लोकतंत्र के मानदंडों पर बड़े प्रश्नचिह्न खड़े हुए हैं। यह केवल राजनीतिक क्षेत्र के लिए चिंता का विषय नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न है। यदि यह एक राजनैतिक खेल है, तब इसमें कोई दोमत नहीं कि यह एक खतरनाक खेल है।

यह केवल राजनीतिक क्षेत्र के लिए चिंता का विषय नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न है

एक ओर जहां पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री के काफिले को सुरक्षा देने के अपने संवैधानिक दायित्वों में असफल रही, वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह की सफाई पेश की, वे अत्यंत संदिग्ध एवं शर्मनाक हैं। यह सर्वविदित है कि एसपीजी की सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री के आवागमन की योजना बहुत पहले तैयार की जाती है और वैकल्पिक मार्गों पर भी सुरक्षा चाक-चौबंद होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री का यह कहना कि प्रधानमंत्री के काफिले का मार्ग अंतिम समय में बदला गया, एक सफेद झूठ है। साथ ही, यह दावा कि प्रधानमंत्री पर कोई खतरा नहीं था, अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। सारा देश जानता है कि पूरे विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध निरंतर लड़ाई लड़ने के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अनेक अंतरराष्ट्रीय आतंकी गुटों के निशाने पर हैं तथा पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब प्रदेश में हाल के महीनों में भी विभिन्न आतंकी गुटों ने शांति भंग करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। परंतु यह अत्यंत शर्मनाक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री पर कोई खतरा नजर नहीं आता। इन बयानों से पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वे अपने पद की गरिमा के साथ न्याय करने में असमर्थ हैं।

इस पूरी घटना की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनटों तक फंसा रहा, वह पाकिस्तान के फायरिंग दायरे में आता है। इसे 'सुरक्षा में चूक' नहीं कहा जा सकता, यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ एक सुनियोजित षड्यंत्र था। ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा किसी भी प्रदेश में राज्य पुलिस के हाथों में होती है जो एसपीजी से समन्वय स्थापित करते हुए काफिले के रूट को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री के काफिले के लिए तय 'रूट' के साथ वैकल्पिक 'रूटों' को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है तथा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों पर सुरक्षा पूर्वाभ्यास भी किया जाता है। इस प्रकार की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं गोपनीयता के उच्च मानदंडों के कारण किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसकी भनक तक लगना असंभव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री के काफिले का 'रूट' पंजाब कानून-व्यवस्था के उच्च स्तर के उकसावे पर बाधित किया गया और राज्य पुलिस ने जान-बूझकर 'रूट' को बाधित होने दिया। यह न केवल अत्यंत घटिया राजनीति थी, बल्कि एक खतरनाक खेल भी था।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी स्वयं को इस आपराधिक कृत्य से दोषमुक्त नहीं कर सकते। इसके अलावा, इस दौरान फोन कॉल का उत्तर नहीं देना, प्रधानमंत्री के प्रदेश में आगमन पर न तो स्वयं उनके स्वागत के लिए आना और न ही अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों को आने देना तथा अपने झूठे दावों से देश को दिग्भ्रमित करने के भी वे दोषी हैं। ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने एवं पंजाब के लिए कई विकास परियोजनाओं का उपहार लेकर गए थे और साथ में फिरोजपुर में भाजपा की एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले थे। पंजाब के मुख्यमंत्री के ये कृत्य न केवल देश के संघीय ढांचे पर हमला है, बल्कि देश के बलिदानियों का अपमान और प्रदेश की जनता के विकास के विरोध में है। उन्होंने न केवल अपने पद की गरिमा को गिराया है, बल्कि संस्थागत व्यवस्थाओं, संवैधानिक मान्यताओं एवं राजनैतिक मूल्यों पर गहरी चोट की है। आज जबकि पूरा देश प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण राजनीति की निंदा कर रहा है, इस घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कांग्रेस को आने वाले दिनों में देश की जनता इस कृत्य के लिए निश्चय ही कड़े दंड देगी। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

सपा ने उत्तर प्रदेश में कुशासन दिया, हमने सुशासन दिया : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर (हापुड़) और बदायूं में जन-विश्वास यात्रा के तहत आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और डबल इंजन सरकार की विकास योजनाओं को विस्तार से रेखांकित करते हुए भारी बहुमत से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री श्री संजीव बाल्यान, क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल, प्रदेश के चुनाव सह-प्रभारी, कैप्टन अभिमन्यु एवं सांसद श्री सतीश गौतम सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बदायूं में आयोजित जनसभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री बी.एल. वर्मा, श्री एस.पी. सिंह बघेल, उप्र सरकार में मंत्री श्री महेंद्र सिंह, छत्रपाल गंगवार और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेता उपस्थित थे।

जन-विश्वास यात्रा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि किसी अन्य राजनीतिक दल में ऐसी हिम्मत नहीं कि वह जन-विश्वास यात्रा निकाल सके क्योंकि उन्होंने जो कहा, ठीक उसके विपरीत कार्य किया। उनका इतिहास विश्वास दिलाने लायक है ही नहीं। हम जन-विश्वास यात्रा के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव 'झांसा यात्रा' निकाल रहे हैं। वे बीच में कभी-कभी यात्रा में निकलते हैं, फिर क्वारंटाइन हो जाते हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कानपुर में मेट्रो रेल सेवा को राज्य को समर्पित कर रहे हैं। कहीं एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं, कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं एम्स बन रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास को जन-जन तक पहुंचाया है। इसे कहते हैं जन-विश्वास। किसी पार्टी का इतिहास ही यह बताने के लिए काफी है कि वह आगे कैसा काम करेगी। हमने विकास किया है, आगे इसे और गति देंगे।

सपा पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सपा ने उत्तर प्रदेश में कुशासन दिया, हमने सुशासन दिया। उन्होंने दंगों का रिकॉर्ड कायम किया, आज दीपोत्सव हो रहा है, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है, विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। सपा की सरकार में हर जिले में एक बाहुबली का राज था। सपा सरकार दंगों, भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जानी जाती है, हमारी सरकार सुशासन और विकास के लिए जानी जाती है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया या तो जेल में मिलते हैं या फिर तड़ीपार हो गए हैं। सपा के शासनकाल में बाहुबली जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते थे, योगी आदित्यनाथ सरकार में जमीनों पर कब्जा करने वाले बाहुबली जेल में हैं और उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश

में बाहुबलियों और भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन हैं और प्रदेश की जनता के अच्छे दिन हैं। सपा की अखिलेश सरकार में लगभग 700 दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर के दंगे में 62 लोगों की मौत हुई, अखिलेश सरकार दंगों की सरकार थी। आज भाजपा की सरकार में यूपी दंगा-मुक्त प्रदेश बना है। पहले उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा, कांवर यात्रा के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, आज कहीं दीपोत्सव मन रहा है तो कहीं कलश यात्रा निकाली जा रही है। 250 करोड़ रुपये से अधिक कैश कहीं और से पकड़ाए, तबीयत किसी और की खराब हो गई। सपा सरकार की पहचान है भ्रष्टाचार, गुंडाराज और माफियाराज जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की पहचान है जनता का सम्मान राज, समता राज और सर्वांगीण विकास राज।

किसान कल्याण के विषय पर चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि देश में कहने को तो कई किसान नेता हुए, लेकिन कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए यदि सबसे अधिक कार्य किसी ने किया है तो वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। पहले कृषि बजट महज 23 हजार करोड़ रुपये का होता था, आज श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में यह 1.21 लाख करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक एकाउंट में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये पहुंचाए हैं। इस निधि की 11वीं क़िस्त प्रधानमंत्रीजी 01 जनवरी, 2022 को जारी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग ढाई करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। डीएपी खाद पर सब्सिडी को 140% बढ़ाया गया। अब डीएपी खाद की एक बोरी 2,400 की बजाय 1,200 रुपये में मिल रही है। ये श्री नरेन्द्र मोदी सरकार हैं जिन्होंने फसलों पर एमएसपी को डेढ़ गुना या इससे भी अधिक बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। सबसे अधिक पेराई भी उत्तर प्रदेश में हो रही है लेकिन हम गन्ना की चर्चा करते हैं, विपक्ष जिन्ना को याद करता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। हमने अखिलेश सरकार का भी लगभग 11 हजार करोड़ रुपये बकाया भुगतान किया है। बसपा की मायावती सरकार में 21 चीनी मिलें औने-पौने दाम में बेच दी गई और 19 चीनी मिलें बंद हो गई। अखिलेश सरकार में भी 11 चीनी मिलें बंद हुई, जबकि भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई जबकि तीन नए चीनी मिल खुले हैं। आज सबसे अधिक एथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल 13 मेडिकल कॉलेज थे, हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और 2022 तक यह संख्या पहुंचकर 42 हो जायेगी। हापुड़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। खुशीनगर और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। पांच एक्सप्रेस-वे हमारी सरकार में बन रहे हैं। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे शुरू हो गया है। दिल्ली-देहरादून मार्ग पर भी काम जारी है। लगभग 55 करोड़ लोगों को देश में 'आयुष्मान भारत' का लाभ मिल रहा है। नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है जो हापुड़, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जायेगी। प्रदेश में रैपिड रेल भी बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जिससे लगभग ढाई करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।

जन-विश्वास यात्रा का समापन समारोह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 जनवरी, 2022 को बस्ती के सक्सेरिया इंटर कॉलेज मैदान और लखनऊ के आईआईएम रोड, दुबग्गा (काकोरी) में पार्टी की जन-विश्वास यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की प्रतीक सपा, बसपा और कांग्रेस को करारा

सबक सिखाते हुए एक बार पुनः भारी बहुमत से भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का आह्वान किया।

विदित हो कि 19 दिसंबर से प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जन-विश्वास यात्रा शुरू हुई थी। गोरखपुर क्षेत्र की जन-विश्वास यात्रा बलिया से शुरू हुई थी जो 3 जनवरी, 2022 को 62 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने के बाद बस्ती में पूरी हुई और अंबेडकरनगर से शुरू हुई अवध क्षेत्र की जन-विश्वास यात्रा अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी से होते हुए 3 जनवरी, 2022 को दुबग्गा (काकोरी), लखनऊ में पूरी हुई। बस्ती के कार्यक्रम में श्री नड्डा के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला, सांसद श्री हरीश द्विवेदी, सांसद श्री जय प्रकाश निषाद, वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री जगदंबिका पाल, श्री अरविंद मेनन, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दुबग्गा, लखनऊ की रैली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर, श्री अशोक टंडन, श्री ब्रजेश पाठक, श्रीमती स्वाति सिंह, श्रीमती रेखा वर्मा, सांसद श्री उपेंद्र रावत, श्री संजय सेठ, श्री मोहसिन रजा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

अखिलेश यादव पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव आजकल 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का झूठा वादा कर रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है कि जो बिजली ही नहीं दे सकता वह बिजली बिल को मुफ्त क्या करेगा! अखिलेश यादव की सरकार में बिजली ही नहीं मिलती थी, आज हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रही है। सौभाग्य योजना के तहत प्रधानमंत्रीजी ने लगभग 2.81 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई, बिजली से वंचित 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 80 लाख घरों में बिजली हमारी डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाई है।

गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, दंगे होते हैं, महिलाओं का सम्मान ख़त्म हो जाता है लेकिन वहीं जब सही जगह बटन दबता है तो नए एम्स बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, सुशासन आता है

उन्होंने कहा कि आजकल महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं लेकिन आपको तब शर्म क्यों नहीं आई जब महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए विवश थीं? हमारी डबल इंजन की सरकार में 11 करोड़ से अधिक इज्जत घर बने और महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1.95 करोड़ इज्जत घर बने।

अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज अखिलेश यादव नए-नए झूठे वादे कर रहे हैं लेकिन आपने अपने पांच साल एक शासन में जो किया, उसे जनता को याद दिलाना जरूरी है। अखिलेश यादव की सरकार में खनन माफिया दनदना रहे थे, आज भी उनके नेता जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह गोमती रिवर फ्रंट में 1,600 करोड़ रुपये के घोटाले की बात आई थी। अखिलेश सरकार ने युवाओं में बांटने के लिए 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे, उसमें केवल सवा छः लाख ही वितरित किये गए, बाकी कहां गए, किसी को नहीं पता। अखिलेश सरकार ने लगभग एक लाख करोड़ रुपए का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था। योगी आदित्यनाथजी की सरकार ने एक लाख स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरित कर दिए हैं, अब एक करोड़ लैपटॉप व स्मार्टफोन वितरित किये जाएंगे। अखिलेश यादव के 5 वर्ष में लगभग 700 दंगे हुए। उस समय महिलाएं असुरक्षित थीं। अखिलेश सरकार ने 15 आतंकियों को बचाने के लिए उन पर से केस हटा लिया था। वह तो भला हो अदालत का जिन्होंने केस हटाने की परमिशन नहीं दी। जांच पूरी होने के बाद उन 15 आतंकियों में से चार को मौत की सजा मिली और बाकियों को उम्र कैद।

उन्होंने कहा कि हम कुर्सी से चिपकने नहीं आए हैं, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर देश को आगे ले जाने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश जब आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिनके नेतृत्व में धारा 370 धराशायी हुआ, ट्रिपल तलाक ख़त्म हुआ, आतंकवाद पर सर्जिकल व एयर स्ट्राइक हुआ और उनके ही कर-कमलों से श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। जनता भूली नहीं है कि रामभक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी, निर्दोषों की हत्या किसने की थी और 25 सितंबर, 2015 को गंगाजी के घाट पर संतों पर लाठीचार्ज किसने किया था? रामभक्तों पर गोलियां और डंडे चलाने वाले आज मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने इन लोगों को मंदिरों में जाने को मजबूर किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में भव्य श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया है और मां विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है।

श्री नड्डा ने उत्तर प्रदेश की महान जनता का आह्वान करते हुए कहा कि गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, दंगे होते हैं, महिलाओं का सम्मान ख़त्म हो जाता है लेकिन वहीं जब सही जगह बटन दबता है तो नए एम्स बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, सुशासन आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है, जिनके आधार पर हम विकास को जन-जन तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर सपा, बसपा और कांग्रेस है जो सत्ता का उपयोग अपने लिए करती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार है जो जो सत्ता का उपयोग गरीबों के आंसू पोंछने के लिए करती है, जन-जन के विकास के लिए करती है। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़

5 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंजाब यात्रा पर थे। उन्हें विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा भाजपा रैली को संबोधित करना था। यात्रा के क्रम में वे बठिंडा पहुंचे थे। यहां से उन्हें हेलिकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। स्मारक से करीब 30 किमी पहले श्री मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा, तो अवरोध उत्पन्न कर मार्ग बाधित कर दिया गया। यह घटना प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्रीजी के रास्ते में जाने दिया गया और उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया।

पंजाब की कांग्रेस सरकार की निकृष्ट सोच और ओछी हरकत उजागर : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 5 जनवरी, 2022 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पर प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधान सभा चुनाव में जनता के हाथों करारी हार के डर से पंजाब में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रमों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश की।

श्री नड्डा ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ऐसा करने में इस बात की भी परवाह नहीं की कि देश के प्रधानमंत्रीजी को देश के महान सपूत सरदार भगत सिंह और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है और राज्य में प्रमुख विकास कार्यों की आधारशिला रखनी है। अपनी निकृष्ट सोच और ओछी हरकतों से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया है कि वह विकास विरोधी है और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी उनके दिल में कोई सम्मान नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह घटना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी। यह बेहद चिंताजनक है। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्रीजी के रास्ते में जाने दिया गया और उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया था कि रास्ता पूरी तरह से साफ है। मामले को और बदतर बनाते हुए कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति, लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी और उन्हें व्यथित करेगी। प्रधानमंत्रीजी की रैली में भाग लेने से लोगों को रोकने के लिए राज्य पुलिस को निर्देशित किया गया था। पुलिस की सख्ती और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत के कारण बड़ी संख्या में बसें भी फंसी हुई थीं।

श्री नड्डा ने कहा कि यह दुःखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दौरा बाधित हो गया, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे।

यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति षड्यंत्र है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा के चूक के मसले पर भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने 5 जनवरी, 2022 को भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा समझौते को लेकर की गई ओछी हरकत पर जमकर निशाना साधा।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि आज देश में एक ऐसी घटना घटित हुई है, जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के दौर में

गृह मंत्रालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री श्री मोदी के सुरक्षा उल्लंघन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी। पंजाब में आज की कांग्रेस-निर्मित घटना इस बात का ट्रेलर है कि यह पार्टी कैसे सोचती है और काम करती है। लोगों द्वारा बार-बार ठुकराए जाने के कारण कांग्रेस पागलपन के रास्ते पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अपने किए पर भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।

- अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

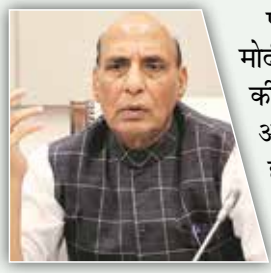

पंजाब में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा के साथ जिस तरह की लापरवाही बरती गयी है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है। राजनीतिक मतभेद के कारण प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की सुरक्षा को ताक पर रखना कांग्रेस की अलोकतांत्रिक सोच और उनकी मानसिकता का परिचायक है।

- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

पंजाब में प्रधानमंत्रीजी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होना दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मामला है। पंजाब के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्रीजी को न पहुंचने देना, यह पंजाब के लोगों का अपमान है।

- नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री

और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सुरक्षा की चूक नहीं हुई, जैसी आज प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हुई। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य भूमि पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। कांग्रेस पार्टी में जो लोग प्रधानमंत्रीजी से घृणा करते हैं, वो आज उनकी सुरक्षा को नाकाम करने के लिए प्रयासरत थे।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास में पहले कभी किसी राज्य में पुलिसकर्मियों को किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के न ही निर्देश दिए गए थे और न ही इसकी सुविधा दी गयी थी। भारतीय जनता पार्टी बार-बार कहती रही है कि बेशक कांग्रेस पार्टी को श्री नरेन्द्र मोदी से नफरत है लेकिन ऐसी नफरत वे देश के प्रधानमंत्री से तो न करें। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से नफ़रत करती है, लेकिन आज उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की निकृष्ट कोशिश की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल के साथ मजाक हुआ है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने उनकी ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की हुई सुरक्षा चूक पर खुशी का इजहार किया है। आखिर किस बात की खुशी है उन्हें कि देश के प्रधानमंत्री को मौत के कगार पर ले गए? जब सुरक्षाकर्मियों ने पंजाब सरकार से संपर्क साधने की कोशिश की, तो पंजाब मुख्यमंत्री के कार्यालय से किसी ने संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार?

श्रीमती ईरानी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्हें ध्वस्त करना है तो चुनाव मैदान में उनका सामना करके दिखाए। ऐसे साजिश रचने की क्या आवश्यकता है? वे लोग जो षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहती हूं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की कोशिश, देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि सब कुछ जानते हुए भी पंजाब पुलिस मूकदर्शक बनी रही। पंजाब में कानून-व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि वहां के डीजीपी

भाजयुमो ने किया प्रदर्शन

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पंजाब में कांग्रेस सरकार के इशारे पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में जानबूझकर की गई गंभीर लापरवाही के विरोध में 6 जनवरी, 2022 को पूरे देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या ने चेन्नई (तमिलनाडु) में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ विशाल प्रदर्शन किया। ऐसे ही अनेक विरोध प्रदर्शन पूरे देशभर में भी हुए, पुडुचेरी में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, गोवा में भी विशाल प्रदर्शन हुआ। हरियाणा में सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए जहां सैंकड़ों भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसे ही लद्दाख में लद्दाख गेट और सदाकत आश्रम में प्रदर्शन हुए। इसी शृंखला में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ और पूरे देशभर में लगभग 950 जिला में भाजयुमो ने विरोध प्रदर्शन किया।

गुरु गोबिंद सिंह के बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' मनाया जाएगा

फाइल फोटो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौ जनवरी को घोषणा की कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। ट्वीट्स की एक शृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों की साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्प के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।

श्री मोदी ने कहा कि 'वीर बाल दिवस' उस दिन मनाया जायेगा, जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी एक दीवार में जिंदा चुनवाये जाने के कारण शहीद हुए थे। इन दोनों महान बालकों ने धर्म के नेक सिद्धांतों से विचलित होने की बजाय मृत्यु का वरण किया।

उन्होंने कहा कि माता गुजरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता तथा आदर्श लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसे विश्व की कल्पना की, जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग उनके बारे में जानें।

प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौ जनवरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर बधाई। उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। मैं हमेशा इस तथ्य को संजोकर रखूंगा कि हमारी सरकार को उनके 350वें प्रकाश उत्सव को मनाने का अवसर मिला है। ■

कहते हैं कि वह पीएमओ को सुरक्षा सहायता और सुरक्षा विवरण प्रदान करने में असमर्थ हैं। दरअसल, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति के षड्यंत्र प्रतीत होता है।

भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र की ओर से पंजाब की कांग्रेस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिसके जवाब का इंतज़ार रहेगा—

सवाल-1: प्रधानमंत्री जिस रूट से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले थे, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध पंजाब पुलिस के पास था। पंजाब पुलिस ने ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्रीजी के सुरक्षा दस्ते को दिया था कि रूट सही है, कोई भी गतिरोध नहीं है। आखिर डीजीपी ने प्रधानमंत्रीजी की सुरक्षा के बारे में गलत आश्वासन क्यों दिया?

सवाल-2: प्रधानमंत्रीजी के पूरे काफिले को जब रोकने का प्रयास किया गया, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग हुई, तो सुरक्षा भंग करने वाले आखिर प्रधानमंत्रीजी की गाड़ियों के पास कैसे पहुंचे?

सवाल-3: राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा का नेतृत्व करने वालों ने प्रधानमंत्रीजी को सुरक्षित करने के किसी भी प्रयास का जवाब क्यों नहीं दिया?

सवाल-4: पंजाब सरकार में किसने फ्लाईओवर पर अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों को प्रधानमंत्रीजी के रूट की जानकारी दी? वीडियो साक्ष्य, जो अब सार्वजनिक रुप से उपलब्ध हैं, ऐसे प्रश्नों को सामने लाते हैं।

सवाल-5: पीएम की मूवमेंट कहां हो रही है, ये साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती, पूरा देश यह बखूबी जानता है। उस दौरान आखिर किसने प्रदर्शनकारियों को वहां भेजा, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। ■

'देश के किसान का आत्मविश्वास देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य है'

10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ट्रांसफ़र की गई 20,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि

जमीनी स्तर के किसानों को सशक्त बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी की। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि ट्रांसफ़र की गई।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने एफपीओ से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कृषि मंत्री एवं किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के पीड़ित लोगों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुःखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं।

श्री मोदी ने महामारी से लड़ने, टीकाकरण और कठिन समय में कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्था करने में राष्ट्र के प्रयासों को याद किया। कमजोर वर्गों को राशन उपलब्ध कराने पर देश 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

उन्होंने चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में नए ऑक्सीजन प्लांट, नए मेडिकल कॉलेज, वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जैसे प्रयासों को गिनाया।

श्री मोदी ने कहा कि आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर आठ प्रतिशत से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया

मोदी सरकार सदैव किसान कल्याण के लिए समर्पित रही है। नव वर्ष 2022 के प्रथम दिन देश के 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की दसवीं किश्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ह्रदय से धन्यवाद करता हूं।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी संग्रह में भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। हमने निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि 2021 में 70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन यूपीआई से किया गया। आज भारत में 50 हजार से ज्यादा स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं। इनमें से 10 हजार स्टार्ट-अप तो पिछले छह महीने में बने हैं।

श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2021 भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का वर्ष भी था। काशी विश्वनाथ धाम और केदारनाथ धाम का सौंदर्यीकरण एवं विकास, आदि शंकराचार्य की समाधि का जीर्णोद्धार, देवी अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति का जीर्णोद्धार, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और धोलावीरा एवं दुर्गा पूजा उत्सव के लिए विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त करने जैसी पहल भारत की विरासत को मजबूत कर रही हैं और पर्यटन एवं तीर्थयात्रा से जुड़ी संभावनाओं को बढ़ा रही हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 मातृ-शक्ति के लिए भी आशावाद का वर्ष था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दरवाजे खोलने के साथ-साथ लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोले गए। पिछले वर्ष लड़कियों की शादी की उम्र को लड़कों के बराबर बढ़ाकर 21 करने के प्रयास शुरू किए गए।

वर्ष 2021 मातृ-शक्ति के लिए भी आशावाद का वर्ष था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दरवाजे खोलने के साथ-साथ लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोले गए। पिछले वर्ष लड़कियों की शादी की उम्र को लड़कों के बराबर बढ़ाकर 21 करने के प्रयास शुरू किए गए

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विश्व का नेतृत्व करते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य दुनिया के सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान को समय से पहले पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में बढ़त ले रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया को नए आयाम देते हुए देश ने चिप निर्माण, सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि अगर आज जारी किस्त को भी शामिल कर लें, तो 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एफपीओ के लाभों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें हर स्तर पर बढ़ावा दे रही है। इन एफपीओ को 15 लाख रुपये तक की मदद दी जा रही है। इसी वजह से पूरे देश में जैविक एफपीओ, तिलहन एफपीओ, बांस क्लस्टर और शहद एफपीओ जैसे एफपीओ सामने आ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज हमारे किसान 'एक जिला, एक उत्पाद' जैसी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और देश एवं वैश्विक स्तर के बाजार उनके लिए खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 हजार करोड़ रुपये के बजट वाले नेशनल पाम ऑयल मिशन जैसी योजनाओं से आयात पर निर्भरता कम हो रही है।

श्री मोदी ने हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में हासिल किए गए मील के पत्थर के बारे में बात की। खाद्यान्न उत्पादन 300 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसी तरह, बागवानी और फूलों की खेती का उत्पादन 330 मिलियन टन तक पहुंच गया। दुग्ध उत्पादन भी पिछले 6-7 वर्षों में लगभग 45 प्रतिशत बढ़ा। लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरीगेशन) के अंतर्गत लाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के रूप में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई, जबकि प्राप्त प्रीमियम सिर्फ 21 हजार करोड़ रुपये का ही था। महज सात वर्षों में इथेनॉल का उत्पादन 40 करोड़ लीटर से बढ़कर 340 करोड़ लीटर हो गया।

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रसायन मुक्त खेती मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक प्रमुख तरीका है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रत्येक किसान को प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं और लाभों से अवगत कराने के लिए कहा। श्री मोदी ने अपने भाषण का समापन करते हुए किसानों से खेती में निरंतर नवाचार करते रहने और स्वच्छता जैसे आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान किया।

किसान सशक्तिकरण के बिना देश का समग्र विकास असंभव है: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 के पहले ही दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ किसानों के ख़ातों में 20 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने को किसान कल्याण को प्राथमिकता देने वाला क़दम बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि किसान सशक्तिकरण के बिना देश का समग्र विकास असंभव है और एक किसान हितैषी सरकार कैसी होती है, ये देश ने पिछले 7 साल से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर अहर्निश प्रयास कर रही मोदी सरकार के रूप में देखा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय पर किसानों को आर्थिक संबल देकर उन्हें कर्जमुक्त रखने का बहुत बड़ा काम किया है। ■

मणिपुर में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 दिसंबर, 2021 को सगोलबंद, मणिपुर में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और डबल इंजन की सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाये गए इनिशिएटिव्स पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती शारदा देवी के साथ-साथ मणिपुर की भाजपा सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मातृशक्ति की अपार भीड़ जनसभा में उमड़ी।

क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मणिपुर और मातृशक्ति में बहुत ही गहरा संबंध है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, साहित्य जगत हो या आजादी की लड़ाई, मणिपुर की महिलायें हमेशा अग्रणी रही हैं। उन्होंने रानी गाइदिनल्यू को नमन करते हुए कहा कि हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारी सरकार उनके सम्मान में एक फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना रही है। मैं इसके लिए केंद्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने कहा कि पांच साल पहले मणिपुर में अराजकता और भय का माहौल था। मणिपुर में श्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अराजकता और भय का माहौल हट चुका है। आज इतनी भारी संख्या में जो मातृशक्ति इस सम्मेलन में उपस्थित हुई हैं, यह समाज का प्रतिबिंब है और समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे समर्थन की बानगी है।

श्री नड्डा ने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में बच्चियों का एनरोलमेंट हुआ है, मातृ वंदन कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश, फ्री डिलीवरी और एंबुलेंस की सुविधा और 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत देशभर में लगभग 11 लाख टॉयलेट्स बने, जबकि मणिपुर में 2.07 लाख टॉयलेट्स का निर्माण हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में लगभग 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, जबकि मणिपुर में लगभग 1.70 लाख गैस कनेक्शन वितरित किये गए। कोरोना कालखंड में मणिपुर में लगभग 10 लाख महिलाओं के एकाउंट में 500 रुपये की तीन किस्तें दी गई। मुद्रा योजना के तहत लगभग 19 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, मणिपुर में भी लाखों महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। स्टैंड-अप योजना से लगभग एक लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि हम Women Development की बात करते हैं, पर मणिपुर में Women-led Development की बात होती है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा भी महिला हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मातृशक्ति के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय देश के इतिहास में जोड़ा है। उन्होंने देश को पहली महिला रक्षा मंत्री, पहली महिला शिक्षा मंत्री, पहली महिला विदेश मंत्री दिया। साथ ही, देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री भी उन्होंने ही बनाया। आज श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में 12 महिला मंत्री हैं। इतना ही नहीं, आज एयरफोर्स में भी महिलायें फाइटर पायलट के रूप में सेवा दे रही हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और सेंट्रल फोर्सेज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में श्री एन. बीरेन सिंह सरकार मणिपुर में डबल स्पीड से विकास कार्य को जन-जन तक पहुंचा रही है। ■

'भारत स्टार्ट-अप में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हब बना है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 दिसंबर, 2021 को काकचिंग, मणिपुर में आयोजित विशाल युवा सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और युवाओं के उत्थान के लिए डबल इंजन की सरकार द्वारा उठाये गए कदमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए जनता से पुनः भारी बहुमत से मणिपुर में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती शारदा देवी, मणिपुर के भाजपा प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा तथा मणिपुर से राज्य सभा सांसद श्री लिसेम्बा सानाजाओबा के साथ-साथ प्रदेश की भाजपा सरकार के कई मंत्री, विधायक, युवा नेता भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि युवाओं के जोश एवं उत्साह से यह तय है कि मणिपुर में पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा भारत के भविष्य हैं, वे हमारी आशा हैं, ताकत हैं जिनके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार कर रहे हैं। जिस तरह से आजाद हिंद फ़ौज ने मणिपुर को आजादी का गेटवे बनाया था, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मणिपुर आत्मनिर्भर भारत का गेटवे बना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवा उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लगभग 70 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। मुद्रा योजना के तहत देश के लगभग 31 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया है जिसका एकमात्र मकसद है है देश के युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रियेटर बनाना, जॉब गिवर बनाना। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्टार्ट-अप में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हब बना है। स्टार्ट-अप्स की शुरुआत के लिए भारत सरकार ने आर्थिक मदद दिए हैं। मणिपुर में श्री एन. बीरेन सिंह ने स्टैंड-अप योजना में राज्य के लगभग 5600 उद्यमियों को जोड़ा है जिस पर लगभग 114 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने पूरे देश में प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है। अटल इनोवेशन मिशन और टिंकरिंग लैब्स जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। देश में 20 इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड के इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बने हैं, जिनमें से प्रत्येक को केंद्र सरकार की ओर से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। देश में 34 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाकर इसे भारतीयता के अनुरूप बनाया गया है। इसमें छात्रों को भाषा और सब्जेक्ट चुनने की फ्लेक्सिबिलीटी है। यह नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए आगे बढ़ने के मार्ग में बाधक नहीं, साधक बनेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि मणिपुर और स्पोर्ट्स एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भारत सरकार लगभग 1000 मेधावी खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये सालाना की सहायता दे रही है। मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मैरीकॉम से लेकर मीराबाई चानू तक मणिपुर ने देश को एक से एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। मैं मणिपुर की मातृशक्ति को भी नमन करता हूं।

उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने बिना रुकावट प्रदेश में विकास को गति दी है। मणिपुर में कांग्रेस की पहचान रही है श्री 'आई (I) अर्थात् इंस्टेबिलीटी, इंसर्जेंसी और इनइक्वलिटी जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए श्री आई का मतलब है— इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन और इंटीग्रेशन। हमने मणिपुर की संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए सबका एक-समान विकास किया।

मणिपुर में विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मणिपुर में हमारी सरकार में लगभग 4200 करोड़ रुपये के खर्च से 16 नए नेशनल हाइवे बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। मणिपुर को ब्लॉकेड की समस्या से निजात मिली है। हमारी सरकार में लगभग 1,300 से अधिक नौजवानों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्रीजी हर 15 दिन पर पीपल्स डे मनाते हैं, हमारे मंत्री, विधायक जनता दरबार लगाते हैं। पहले जनता को किसी भी काम के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे आज सरकार 'गो टू हिल्स' और 'गो टू विलेज' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के जन-जन तक पहुंच रही है। ■

लद्दाख एवं लक्षद्वीप प्रदेश भाजपा अध्यक्षों की नियुक्तियां

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जनवरी 2022 को लद्दाख एवं लक्षद्वीप प्रदेश भाजपा अध्यक्षों की नियुक्ति की। श्री फुनचोक स्टेनजिन एवं श्री केएन कास्मिकोया क्रमशः लद्दाख एवं लक्षद्वीप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए गए हैं।

हम उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की ओर बढ़ रहे हैं: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 26 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के कासगंज और औराई में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश की जनता से राज्य में विकास के सतत प्रवाह के लिए एक बार पुनः भारी बहुमत से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, एटा से लोक सभा सांसद श्री राजवीर सिंह (राजू भैया), केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, सांसद संघमित्रा मौर्य, सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप और ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में तीन 'पी' (P) अर्थात् परिवारवाद, पक्षपात और पलायन का बोलबाला था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में परिवारवाद, पक्षपात और पलायन की राजनीति का अंत हुआ है और विकासवाद की राजनीति प्रतिष्ठित हुई है। सपा की सरकार आती थी तो एक जाति का विकास होता था, बसपा की सरकार आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की अवधारणा से काम करती है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी काशी से संसद सदस्य हैं। औरंगजेब के समय से बाबा विश्वनाथ का दरबार सूना पड़ा हुआ था। श्रद्धालुओं में कसक थी कि बाबा का दरबार भव्य क्यों नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार ऐसे सजाया है कि हर देशवासी इसको देखकर गद्गद हैं। आज मां गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करना है तो बीच में कुछ भी नहीं आता।

श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अब यूनिवर्सिटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, उद्योग-धंधे लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश गुंडाराज से मुक्त हो गया है। अखिलेशजी, आपके पांच वर्षों के शासन काल में उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा दंगे हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है दंगा करने की। भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार में डकैती में 70 प्रतिशत, लूट में 65 प्रतिशत, अपहरण-फिरौती में 50 प्रतिशत और बलात्कार के मामलों में भी लगभग 65 प्रतिशत की कमी आई है। माताओं-बहनों को सुरक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

बुंदेलखंड में औराई में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह

ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का लगभग 36,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ़ किया। वर्षों से केन-बेतवा परियोजना बंद पड़ी थी, इसे फिर से शुरू करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। बुंदेलखंड में डिफेन्स कॉरिडोर लेकर प्रधानमंत्रीजी आये। लगभग 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में झांसी में 600 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास किया है। बुंदेलखंड में लगभग 49,000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई योजनाएं श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में पहुंची है। चित्रकूट और ललितपुर में दो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। झांसी में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बन रहा है।

मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 30 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश की जनता से प्रदेश में एक बार पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। मुरादाबाद के कार्यक्रम में श्री शाह के साथ प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्य के भाजपा चुनाव सह-प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु, श्री संजय भाटिया, क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल, राज्य सारकार में मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर, श्री सतीश गौतम, श्री सुरेंद्र सिंह नागर एवं श्री सतपाल सैनी भी उपस्थित थे। अलीगढ़ के कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अश्वनी त्यागी, क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी, केंद्रीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल, श्री सुरेश राणा, श्री सतीश गौतम आदि भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। उन्नाव की रैली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, सांसद साक्षी महाराज,

श्री राजवीर सिंह राजू भैया, श्री अमरपाल मौर्य, श्री विजय बहादुर पाठक सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि बुआ-बबुआ ने यूपी में वर्षों राज किया लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। पश्चिमी यूपी का बुरा हाल करके रख दिया था बुआ-बबुआ की सरकारों ने। बाबू हुकुम सिंहजी को पलायन के विरोध में आंदोलन करना पड़ा। आज डबल इंजन की सरकार में जनता का पलायन कराने वाले खुद पलायन कर रहे हैं। विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हाथी और साइकिल वालों ने अपने शासन काल में भ्रष्टाचार के नोटों से अपने घर की बोरियां भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता को बुआ-बबुआ-बहन का निजाम नहीं चाहिए। बुआ-बबुआ-बहन की निजाम (NIZAM) का मतलब है - 'N' से नसीमुद्दीन, 'I' से इमरान मसूद, 'ZA' से आजम खान और 'M' से मुख्तार अंसारी। उनका निजाम भ्रष्टाचार, अपराध, गुंडागर्दी और अराजकता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आजम खान और मुख्तार अंसारी के शासन की जगह श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी का शासन वापस लाने का मन बना लिया है।

उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को एक नए प्रकार का लैब (LAB) बनाया जिसका मतलब है 'L' से लूट, 'A' से आतंकवाद और 'B' से भ्रष्टाचार। इन पार्टियों ने पूरे प्रदेश को लूटा और इत्र वाले जैसों की बोरियां भरने का काम किया। यूपी में आजम खान की दबंगई से कौन वाकिफ नहीं है? आजम खान ने 1,000 हेक्टेयर भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में जेल की सलाखों के पीछे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जेल में आजम खान से मिलने कौन जाता है। यदि गलती से भी प्रदेश में सपा सरकार आई तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर आजम खान जैसे भू-माफिया को जेल में ही रखना है तो प्रदेश में पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार बनानी होगी।

उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अब यूनिवर्सिटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, उद्योग-धंधे लग रहे हैं

मुरादाबाद में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मुरादाबाद में फिर से पीतल उद्योग फल-फूल रहा है। मुरादाबाद को आर्थिक गलियारे से भी जोड़ा गया है। लगभग 494 किमी दिल्ली-लखनऊ आर्थिक गलियारे का विकास किया जा रहा है। अलीगढ़-मुरादाबाद और मुरादाबाद-बरेली कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद में 6 ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं।

अयोध्या और संत कबीर नगर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 31 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश में प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या और संत कबीर नगर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और योगी आदित्यनाथजी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को विकास और आस्था के संरक्षण का अग्रदूत बताते हुए प्रदेश की जनता से एक बार फिर यूपी में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि बुआ-बबुआ के शासन में हमारी आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी हर एक आस्था के स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जब देश के जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाई, श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो आज श्रीराम जन्मभूमि पर ही रामलला का मंदिर बन रहा है। भगवान् श्रीराम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा ने अपने शासन में ढेर सारे प्रयत्न किए। आप सभी को याद होगा, इन लोगों ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी। राम सेवकों पर डंडे बरसाए थे, रामसेवकों को मारकर सरयू नदी में बहा दिया गया था। यह सोचने का समय है कि आखिर रामलला को इतने दिन तक क्यों टेंट में रहना पड़ा? किसने राम मंदिर के निर्माण को रोककर रखा था? रामभक्तों और कारसेवकों पर किसने गोलियां चलाई, किसने रामभक्तों पर डंडे चलवाए? रामनवमी और दीपोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रमों को किसने बंद किया था? इस भूमि ने वर्षों तक प्रभु श्रीरामलला के जन्मस्थान के लिए संघर्ष किया है। यहां अनेक बार विनाश भी हुआ, निर्माण भी हुआ। मगर हर बार विनाश पर निर्माण ने विजय प्राप्त की। भाजपा की सरकार में अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापस दिलाने का काम किया है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के नाम से जोड़कर श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जो दुनिया के सभी स्थानों से राम भक्तों को अयोध्या लाने का काम करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण हुआ है। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है।

संत कबीर नगर में पूर्वांचल में डबल इंजन की सरकार में हुए विकास कार्यों को विस्तार से बताते हुए श्री शाह ने कहा कि गोरखपुर में एम्स बना है, कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। पिपराइच, गोरखपुर और बस्ती में 27-27 मेगावाट के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर में खाद कारखाने को दुबारा शुरू किया गया है। गोरखपुर में कम्प्रेस्ड बॉयो गैस प्लांट लगाया जा रहा है। गोरखपुर में मेट्रो का डीपीआर बन गया है। 1,500 किमी लंबा वाराणसी-हल्दिया जलमार्ग बनाय गया है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए पूर्वांचल में रेल रूटों का विद्युतीकरण किया गया है। गोरखपुर में दिमागी बुखार के संबंध में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। ■

लोकतंत्र की हत्यारी है केसीआर सरकार

तेलंगाना सरकार ने एक आदेश संख्या 317 जारी किया है। यह आदेश शिक्षकों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में उनके हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर तेलंगाना प्रदेश भाजपा विरोध-प्रदर्शन कर रही है। इससे केसीआर सरकार बौखला गई है। गत 2 जनवरी को करीमनगर पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बांदी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। श्री कुमार की इस अनैतिक एवं अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा ने आंदोलन और तेज कर दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमारजी की गिरफ्तारी अनैतिक एवं अलोकतांत्रिक: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 4 जनवरी, 2022 को प्रदेश भाजपा कार्यालय, नामपल्ली (हैदराबाद), तेलंगाना में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और लोकतंत्र की हत्यारी केसीआर सरकार पर जमकर हमला किया। इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और प्रदेश भाजपा प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ के साथ कई वरिष्ठ पार्टी नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बांदी संजय कुमार की अनैतिक और अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के विरोध में श्री नड्डा एक शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च करने वाले थे लेकिन तेलंगाना सरकार ने भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता के डर से उनके हैदराबाद पहुंचने से पहले ही धारा 144 लगा दिया।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री बांदी संजय कुमार की अनैतिक एवं अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के विरोध में तथा तेलंगाना के कर्मचारियों एवं प्रदेश की जनता के हित में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने आया था लेकिन एयरपोर्ट पर ही प्रदेश के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करने का सरकारी आदेश है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। मैंने कहा सभी नॉर्म्स का अनुसरण करूंगा और इसके हिसाब से महात्मा गांधीजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करूंगा और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए काम करूंगा। मैंने उनसे कहा कि हम कोविड पर सरकार की ओर से जारी सभी मानदंडों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पार्टी का विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं है।

उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार गैर-प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है। यह एक मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पार्टी है। पिछले दो दिनों में जिस तरह केसीआर सरकार ने तेलंगाना में लोकतंत्र की हत्या की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है। केसीआर सरकार तानाशाही सरकार है जो वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के सिद्धांत पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति की विचारधारा के खिलाफ शुरू से लड़ती आई है और हम तब तक इसके खिलाफ लड़ती रहेगी जब तक कि हम तेलंगाना की इस अलोकतांत्रिक टीआरएस सरकार को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार का जीओ 317 पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी और जन-विरोधी आदेश है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते यह हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कर्मचारियों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, आदिवासियों के लिए उनकी लड़ाई लड़ें और इसे निर्णायक मोड़ तक ले जाएं। हम शांतिपूर्ण तरीके से जनता की आवाज को उठा रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बांदी संजय कुमार ने कोरोना के नियमों के मुताबिक़ करीमनगर में अपने एमपी कार्यालय में केसीआर सरकार की आदेश संख्या 317 के खिलाफ रात्रि जागरण का कार्यक्रम बनाया था। एक तो पहले शिक्षकों को इस कार्यक्रम में जाने से रोका गया, फिर अमानवीय एवं क्रूर तरीके से कटर से कार्यालय के गेट को काटा गया, अश्रु गैस के घोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी कई महिला कार्यकर्ताओं को भी गंभीर चोटें आई। यह वाकई शर्मनाक है! केसीआर जिस तरह से तानाशाही व्यवहार कर रहे हैं, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, कम है।

उन्होंने कहा कि केसीआर बौखला गए हैं और अपना आपा खो चुके हैं। जब से दुबग्गा में भाजपा की जीत का धमाका हुआ है और हुजूराबाद में हुजूर को हार का फटका लगा है, तब से शायद केसीआर सरकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। हम केसीआर की तानाशाही, भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसे अंजाम तक लेकर जायेंगे। ■

10 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा

यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में, अन्य राज्यों में एक चरण में मतदान; 10 मार्च को परिणाम

चुनाव आयोग ने 08 जनवरी, 2022 को गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। घोषणाओं के अनुसार उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सात चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होगा।

पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही दिन 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में चुनाव 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में होंगे।

पांच राज्यों के सभी 690 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतगणना 10 मार्च को की जाएगी, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 18.34 करोड़ है।

ओमाइक्रोन खतरे को देखते हुए 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैलियां, वाहन रैलियां और जुलूस के साथ-साथ अन्य किसी रैलियों की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग 15 जनवरी को स्थिति की समीक्षा करेगा और उसके बाद चुनाव प्रचार की अनुमति देने पर फैसला करेगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और राज्य के मुख्य सचिव, चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ कोविड दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। उम्मीदवारों को एक हलफनामा भी जमा करना होगा कि वे दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। विजय जुलूसों पर भी रोक रहेगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव घोषणा का स्वागत किया

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस वक्तव्य में निर्वाचन आयोग की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधान सभा चुनाव कराने की तिथियों की घोषणा किए जाने का मैं स्वागत करता हूं।

मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे चुनाव आयोग द्वारा बताई गई कोविड और अन्य सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरी ताक़त से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें।

आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और सेवा एवं विकास के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ■

विधानसभा चुनाव कार्यक्रम

राज्य	मतदान की शुरुआत	मतदान का अंत	मतदान के दिवस	सत्ताधारी दल	कुल सीटें
उत्तर प्रदेश	फरवरी 10	मार्च 7	7	भाजपा	403
पंजाब	फरवरी 14	फरवरी 14	1	कांग्रेस	117
उत्तराखंड	फरवरी 14	फरवरी 14	1	भाजपा	70
मणिपुर	फरवरी 27	मार्च 3	2	भाजपा	60
गोवा	फरवरी 14	फरवरी 14	1	भाजपा	40
मतगणना:10 मार्च					

देश में 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू

देश में 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को तीन जनवरी से कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक दी जानी शुरू कर दी गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 दिसंबर को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि इस आयुवर्ग के बच्चों को कोविड-19 रोधी 'कोवैक्सिन' टीके की खुराक दी जाएगी।

भारत के औषधि महानियंत्रक ने 24 दिसंबर को कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी 'कोवैक्सिन' टीके के आपात स्थिति में उपयोग की स्वीकृति दे दी थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किशोरों को टीका लगवाने पर बधाई दी। श्री मोदी ने इनके माता-पिता को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज हमने कोविड-19 के खिलाफ अपने किशोरों को सुरक्षित करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। टीका लगवाने वाले 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के मैं अपने सभी किशोर मित्रों को बधाई देता हूं। मैं उनके माता-पिता को भी बधाई देता हूं। मैं अन्य किशोरों से भी आग्रह करता हूं कि वे आने वाले दिनों में टीके लगवा लें।

इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के अंतर्गत आज से देशभर में 15 से 18 आयुवर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गयी है। हमारे यंग इंडिया को कोरोना का सुरक्षा कवच देने हेतु मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। ■

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 रोधी टीकों कोवोवैक्स, कोर्बेवैक्स के आपात स्थिति में इस्तेमाल को दी स्वीकृति

'कोर्बेवैक्स' भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट कोविड-19 रोधी टीका है। यह भारत में निर्मित तीसरा टीका है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने 28 दिसंबर को बताया कि केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (एसआईआई) के कोविड-19 रोधी टीके 'कोवोवैक्स' और 'बायोलॉजिकल ई' कम्पनी के टीके 'कोर्बेवैक्स' को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति दे दी। साथ ही, कोविड-19 रोधी दवा 'मोलनुपिराविर' (गोली) के आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग को भी अनुमति मिल गई है।

श्री मांडविया ने ट्वीट किया, ''मुबारक हो भारत। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करते हुए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एक दिन में तीन स्वीकृति दी है। कोवोवैक्स, कोर्बेवैक्स टीके और दवा 'मोलनुपिराविर' को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति दे दी है।

इस मंजूरी के साथ देश में आपात स्थिति में उपयोग होने वाले कोविड-19 रोधी टीकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, जायडस कैडिला का जायकोव-डी, रूस का स्पुतनिक वी और अमेरिका का मॉडर्ना एवं जॉनसन एंड जॉनसन वे अन्य छह टीके हैं, जिन्हें भारतीय दवा नियामक पहले ही आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है।

श्री मांडविया ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि 'कोर्बेवैक्स' भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट कोविड-19 रोधी टीका है। इस हैदराबाद की 'बायोलॉजिकल ई' कम्पनी ने बनाया है। यह हैट्रिक है। यह भारत में निर्मित तीसरा टीका है। ■

पी-8आई विमान का आईएनएस हंसा से संचालन शुरू

भारतीय नौसेना के बोइंग पी-8 आई विमानों का आईएनएस हंसा से 30 दिसंबर, 2021 को दो विमानों के आगमन के साथ संचालन शुरू हो गया। विमानों को स्वदेशी उपकरण लगाने और उड़ान स्वीकृति परीक्षणों के बाद शामिल किया गया। विमानों के आगमन पर मिग 29 के फॉर्मेशन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

भारतीय नौसेना ने 2013 में आठ पी-8आई विमानों के पहले बैच का अधिग्रहण किया था जो आईएनएस राजाली, अरक्कोनाम में तैनात हैं। चार अतिरिक्त विमानों के दूसरे बैच का बेस इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 होगा, जिसे आईएनएस हंसा पर तैनात किया जायेगा।

दिसंबर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये रहा

दिसंबर, 2021 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 13% अधिक और दिसंबर, 2019 में जीएसटी राजस्व से 26% अधिक है

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक जनवरी को जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिसंबर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 22,578 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 28,658 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 69,155 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 37,527 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 9,389 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 614 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 25,568 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 21,102 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर, 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 48,146 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 49,760 करोड़ रुपये है।

दिसंबर, 2021 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 13% अधिक और दिसंबर, 2019 में जीएसटी राजस्व से 26% अधिक है। महीने के दौरान माल के आयात से राजस्व 36% अधिक था और राजस्व घरेलू लेनदेन से (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 5% अधिक है।

अक्टूबर, 2021 (7.4 करोड़) के महीने की तुलना में नवंबर, 2021 (6.1 करोड़) के दौरान ई-वे बिलों की संख्या में 17% की कमी के बावजूद महीने में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के करीब है। केंद्रीय और राज्य दोनों कर प्राधिकरणों द्वारा बेहतर कर अनुपालन और बेहतर कर प्रशासन के कारण यह संभव हुआ।

चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.15 लाख करोड़ रुपये था। आर्थिक सुधार के साथ चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। राजस्व में सुधार शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए परिषद् द्वारा उठाए गए विभिन्न युक्तिकरण उपायों के कारण भी हुआ है। उम्मीद है कि राजस्व में सकारात्मक रुझान अंतिम तिमाही में भी जारी रहेगा। ■

3.68 करोड़ लोगों ने 'अटल पेंशन योजना' में कराया नाम दर्ज

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में अभी तक 3.68 करोड़ लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पांच जनवरी को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस वित्त वर्ष में 65 लाख से अधिक लोगों ने इसमें नामांकन किया है, जो योजना के शुरू होने से इस अवधि में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है। नामांकन के अलावा पुरुष से महिला सदस्यता अनुपात 56:44 में सुधार हो रहा है और प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) लगभग 20,000 करोड़ रुपये है।

9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असंगठित क्षेत्रों में नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई की शुरुआत की थी।

दरअसल, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने का यह अद्भुत काम सार्वजनिक और निजी बैंकों के अथक प्रयासों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, डाक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा दिए गए समर्थन से संभव हो सका है।

गौरतलब है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा एपीवाई की सदस्यता ली जा सकती है, जिसके पास बैंक खाता है। इसके तीन प्रमुख लाभ हैं। सबसे पहला इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान की जाती है। दूसरा यह है कि अभिदाता (बीमित व्यक्ति) की मृत्यु होने पर जीवन-साथी को जीवन भर के लिए पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है और अंत में अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में पूरी पेंशन राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। ■

12,031 करोड़ रुपये की हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II को मिली मंजूरी

इस योजना से सात राज्यों— गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में छह जनवरी को अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) के लिये हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II की योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब-स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पियर (एमवीए) ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने को मंजूरी दी गई। इस योजना से सात राज्यों— गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी।

इस योजना को कुल 12,031.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परियोजना के 33 प्रतिशत के बराबर यानी 3970.34 करोड़ रुपये होगी। पारेषण प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तैयार किया जायेगा। केंद्रीय वित्तीय सहायता से राज्यांतरिक पारेषण शुल्कों का समायोजन करने में मदद मिलेगी और इस तरह बिजली की कीमत को कम रखा जा सकेगा। लिहाजा, बिजली के अंतिम उपयोगकर्ता– देश के नागरिकों को ही सरकारी सहयोग से फायदा पहुंचेगा।

इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह योजना देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करेगी तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत वृद्धि को बढ़ावा देगी। इससे बिजली और अन्य सम्बंधित सेक्टरों में कुशल और अकुशल, दोनों तरह के कामगारों के लिये बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

यह योजना जीईसी-चरण-I के अतिरिक्त है, जो ग्रिड एकीकरण तथा लगभग 24 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के संदर्भ में आंध्रप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में पहले से चल रही है। उम्मीद है कि 2022 तक यह पूरी हो जायेगी। जिन सब-स्टेशनों के पास 4056.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सहित 10,141.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पारेषण परियोजनाएं हैं, यह योजना उन सब-स्टेशनों में 9,700 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त पारेषण लाइनों और उनमें 22,600 एमवीए की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिये है। ■

अक्टूबर, 2021 में खनिज पदार्थों का उत्पादन 20.4 प्रतिशत बढ़ा

जिन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन में अक्टूबर, 2020 की तुलना में अक्टूबर, 2021 में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, उनमें सोना (55.7%), लिग्नाइट (49.7%), मैग्नेसाइट (33.1%), क्रोमाइट (30%), प्राकृतिक गैस (यू) (25.8%) और कोयला (14.5%) शामिल हैं

केन्द्रीय खान मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर, 2021 (आधारः 2011-12=100) महीने के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज पदार्थों के उत्पादन का सूचकांक 109.7 पर रहा, जो पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 20.4 % अधिक था। अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.4 प्रतिशत बढ़ी है।

अक्टूबर, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर थाः कोयला 639 लाख टन, लिग्नाइट 37 लाख टन, पेट्रोलियम (कच्चा) 25 लाख टन, बॉक्साइट 1792 हजार टन, क्रोमाइट 130 हजार टन, सोना 109 किलो, लौह अयस्क 190 लाख टन, सीसा सांद्र 33 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 202 हजार टन, जस्ता सांद्र 137 हजार टन, चूना पत्थर 319 लाख टन, फास्फोराइट 127 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन और हीरा 24 कैरेट।

जिन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन में अक्टूबर, 2020 की तुलना में अक्टूबर, 2021 में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, उनमें सोना (55.7%), लिग्नाइट (49.7%), मैग्नेसाइट (33.1%), क्रोमाइट (30%), प्राकृतिक गैस (यू) (25.8%) और कोयला (14.5%) शामिल हैं। ■

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

(गतांक से...)

लोक शिक्षा

शालेय अध्ययन के अतिरिक्त लोक-संस्कार, स्वाध्याय, लोकमत परिष्कार भी शिक्षा के साधन हैं। इस दृष्टि से रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, संगीत तथा पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, क्लबों आदि का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इनकी योग्य व्यवस्था की ओर राज्य को ध्यान देना चाहिए।

रेडियो और टेलीविजन को सरकारी विभाग के स्थान पर एक स्वायत्त निगम के रूप में चलाना चाहिए।

चित्रपट लोक-शिक्षा का एक अत्यंत प्रभावी साधन है। अभिव्यक्ति के इस माध्यम का विकास करना चाहिए। किंतु शासन को यह ध्यान रखना चाहिए कि चित्रपट लोकमत-परिष्कार तथा सुरुचि पैदा करने के साधन बनने के स्थान पर लोगों की रुचि बिगाड़नेवाले न बनें।

विदेश नीति

राष्ट्र के उदात्त हितों का संरक्षण ही किसी देश की विदेश नीति का प्रमुख आधार है। भारतीय राष्ट्र की प्रकृति और परंपरा साम्राज्यवादी विस्तारवाद के प्रतिकूल मानव की समानता और आत्मीयता के आधार पर विश्व-एकता की रही है। विश्व शांति और विश्व की एकता भारत की राष्ट्रीय मनीषा है। जब तक विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कायम है, जब तक रंग, धर्म और विचारों के भेद के आधार पर दूसरों को हेय समझने की प्रवृत्ति मौजूद है, जब तक राष्ट्रों के बीच भारी आर्थिक विषमताएं और उनके कारण शोषण विद्यमान है और जब तक दुनिया में युद्ध और शांति की ठेकेदारी दो-चार बड़े राष्ट्रों के पास है, तब तक विश्व में तनाव कम नहीं होंगे तथा हम सदैव ही एक कगार पर खड़े रहेंगे। आवश्यकता है कि पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र हों, मानवाधिकारों की सर्वत्र मान्यता हो, विश्व को समान स्तर पर लाया जाए, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग का क्षेत्र विस्तृत हो तथा अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक सबल, प्रातिनिधिक एवं न्याययुक्त आधार पर विकसित हो। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मोरचों का विकास भी आवश्यक है, जहां राज्यों के शासकीय प्रतिनिधियों के स्थान पर जन प्रतिनिधि एकत्र होकर मोरचों में राष्ट्र-राष्ट्र के बीच विद्यमान खाई को पाट सकें। भारतीय दर्शन विश्व की विविधता को स्वीकार करता है। अतः भारतीय जनसंघ प्रत्येक राष्ट्र के मूलभूत अधिकार को मानता है कि वह अपनी जीवन पद्धति का स्वयं अपनी इच्छानुसार निर्माण करे तथा इस विचार का विरोध करता है कि सब एक ही सांचे में ढल जाएं।

विदेशों से संबंधों का आधार

विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों का निर्धारण किसी एक मोटे नियम के अधीन नहीं हो सकता। सबकी मित्रता और सद्भावना के इच्छुक भारत को मूलतः सम-सहयोग की नीति लेकर चलना होगा। बिना शक्ति और पौरुष के शांति की आकांक्षा दुर्जनों को बढ़ावा देनेवाली और अंत में शांति के लिए घातक होती है। भारत को अपनी विदेश नीति तेजस्वी बनानी होगी। अंतिम लक्ष्यों को सामने रखते हुए उसे परिस्थिति के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों के साथ शत्रु-मित्र भावों का निर्धारण यथार्थवादी आधार पर करना होगा। किसी भी एक अपरिवर्तनीय नीति से बंधे रहना अनीतिमत्तापूर्ण होगा। विश्व को दो शक्ति गुटों के बीच बंटा मानकर किसी के साथ लगाव या तटस्थता का विचार बीते दिनों की बात तथा अयथार्थपूर्ण है।

आक्रांत भू-भाग की मुक्ति

कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के स्वाभाविक शत्रु हैं। दोनों ने भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करके देश के बड़े भू-भाग पर बलात् अधिकार कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का अहित ही दोनों की नीतियों का प्रमुख लक्ष्य है। भारत का प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपने खोए हुए भागों को वापस ले तथा दोनों की आक्रामक प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करे।

पाकिस्तान के प्रति दृढ़ता

पाकिस्तान की जनता मूलतः भारतीय राष्ट्र का अंग है। वह

पृथकतावादी राजनीतिक शक्तियों का शिकार बनकर अलग हुई है। पाकिस्तान की निर्मिति के बाद से वह बराबर पीड़ित है। जिस स्वर्ग की उसे आशा दिखाई गई थी, वह मृग मरीचिका सिद्ध हुई। पाकिस्तान के शासक भारत-विरोधी भावनाएं भड़काकर अपना आसन स्थिर करने की नीति लेकर चल रहे हैं। भारत द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति ही उनका सबसे बड़ा बल है। भारत यदि दृढता की नीति अपनाए तो पाकिस्तानी विरोध का बुलबुला अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता।

कम्युनिस्ट चीन का संकट

कम्युनिस्ट चीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक संकट बना हुआ है। सभी शांतिवादी एवं सह-अस्तित्व के पुजारी देशों के सहयोग से कम्युनिस्ट चीन की विस्तारवादी एवं युद्धलोलुप प्रवृत्ति का विरोध करना होगा। तिब्बत, सिंक्यांग, मंचूरिया और मंगोलिया की स्वतंत्रता फारमोसा सरकार की मान्यता तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की चीन प्रभाव से मुक्ति इस दृष्टि से आवश्यक है।

उत्पादन वृद्धि के बिना देश की समृद्धि संभव नहीं। किंतु समृद्धि की साधना और फल में सभी लोग साझीदार हों, इस हेतु हमें समतर वितरण का भी ध्यान रखना होगा

सांस्कृतिक संबंधों का पुनरुज्जीवन

दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अन्य देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इन संबंधों को पुनरुज्जीवित कर सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

भारतीय प्रवासी

विश्व के अनेक देशों में भारतीय प्रवासी विभिन्न कारणों से जाकर बसे हैं। उन देशों के विकास में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन देशों की स्वतंत्रता के बाद कहीं-कहीं उनके साथ विभेदपूर्ण व्यवहार हुआ है, जिससे वे भविष्य के प्रति आशंकित हैं। भारत का यह दायित्व है कि उन प्रवासियों को समान अधिकार प्राप्त हों, जिससे वे उन देशों की प्रगति में अपना समुचित योगदान कर सकें।

अफ्रीकी देशों से संबंध

अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता सदैव से भारत की रुचि और समर्थन का विषय रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उनके साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। इन स्वतंत्र देशों के साथ सहयोग और मित्रता के संबंध सुदृढ़ करने की नीति बढ़नी चाहिए।

आर्थिक नीति

भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था विशृंखलित है। वह न तो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है और न समाज के सुरक्षा सामर्थ्य की गारंटी दे सकती है। उसका पुनर्गठन करना होगा।

स्वदेशी का मंत्र

उत्पादन वृद्धि के बिना देश की समृद्धि संभव नहीं। किंतु समृद्धि की साधना और फल में सभी लोग साझीदार हों, इस हेतु हमें समतर वितरण का भी ध्यान रखना होगा। वितरण को सुधारे बिना न तो आज का निर्धन धनवान् होने का अनुभव कर सकेगा और न उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक क्षमता और संकल्प जुटा सकेगा। पैदा माल की खपत के लिए बाजार का विस्तार जनसामान्य की क्रयशक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि से ही संभव है।

अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने तथा उत्पादन वृद्धि के लिए पूंजी-निर्माण आवश्यक है। पूंजी के लिए बचत और साहस चाहिए। भारत में अधिकांश लोगों का जीवन स्तर इतना नीचा है कि उपभोग को टालकर बचत की गुंजाइश ही नहीं। साथ ही, परानुकरण से उत्पन्न दिखावा करने की प्रवृत्ति तथा जीवन-मूल्यों में परिवर्तन के कारण जीवन स्तर की धारणा में भी अंतर आया है। हमारी उपभोग-प्रवणता, गुण और मात्रा दोनों में, बड़ी तेजी से बदल रही है। फलतः पुराने धंधों में बेकारी और विपूंजीकरण तथा नए में अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। आधुनिकीकरण के नाम पर पाश्चात्यीकरण तेजी से आ रहा है। सामाजिक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में भी इससे अनेक समस्याएं तथा अवांछनीय प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि स्वदेशी के मंत्र का पुनरुच्चार किया जाए। इससे आवश्यक संयम एवं स्वावलंबन का भाव जागेगा तथा अनावश्यक रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भरता के व्यामोह तथा उसके प्रभाव से बचेंगे।

नियोजन

राष्ट्र के साधनों को न्यूनतम काल में अधिकतम लाभ के लिए प्रयुक्त करने की दृष्टि से आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है। किंतु योजना साधन है, साध्य नहीं। उसका निर्माण राज्य की स्थायी निष्ठाओं की मर्यादाओं के अंतर्गत ही करना होगा। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य वे निष्ठाएं हैं, जिनके प्रतिकूल अर्थोत्पादन की कोई योजना स्वीकार नहीं की जा सकती। वास्तव में ये मर्यादाएं नियोजकों के मार्ग में रुकावट नहीं, बल्कि उनके संबल हैं। यदि उनका सही-सही उपयोग किया जाए तो उनसे राष्ट्र के सामूहिक प्रयत्नों को भारी बल मिल सकता है। कल की समृद्धि के लिए आज के कष्टों की प्रेरणा केवल आर्थिक उद्देश्यों से नहीं मिल सकती। जन-मन में योजना की सिद्धि की आकांक्षा जाग्रत् करने के लिए उसे आदर्शवादी बनना होगा, किंतु उसके लक्ष्य जनता के संभव सामर्थ्य की कल्पना कर यथार्थ की ठोस भूमि पर ही निर्धारित करने चाहिए। ■

(क्रमशः...)

स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भाजपा नेता के. अय्यप्पन पिल्लई का 107 की आयु में स्वर्गवास

स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री के. अय्यपन पिल्लई का 05 जनवरी, 2022 को केरल के तिरुवनंतपुरम में स्वर्गवास हो गया। वह 107 वर्ष के थे।

श्री पिल्लई ने 1942 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए। वह श्री मूलम प्रजा सभा के सदस्य थे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे पुराने सदस्यों में से एक थे।

श्री पिल्लई के स्वर्गवास के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट किया, "अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और केरल भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता के. अय्यप्पन

पिल्लई जी के स्वर्गवास के बारे में जानकर दुःख हुआ। उन्होंने निःस्वार्थ रूप से अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"

महात्मा गांधी द्वारा राजनीति में प्रवेश करने की सलाह दिए जाने के बाद श्री पिल्लई ने त्रावणकोर के नवगठित विधानमंडल में तिरुवनंतपुरम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा।

वह भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार थे और वास्तव में महात्मा गांधी ने उन्हें चुनावी राजनीति में प्रवेश करने की सलाह दी थी।

श्री के. अय्यपन पिल्लई 1981 में नव निर्मित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और तब से केरल की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे। 'कमल संदेश' पत्रिका शोक संतप्त परिवार और उनके शुभिचंतकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। ■

देबदत्त बरकाताकी नहीं रहे

प्रसिद्ध शिक्षाविद्, असम ज्ञान विज्ञान समिति के संस्थापक, असमिया बीजेपी बार्ता (असम भाजपा का मुखपत्र) के संपादक, सामाजिक कार्यकर्ता और असम भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. देबदत्त बरकाताकी का 23 नवंबर, 2021 को कोविड-19 की बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। रामकृष्ण मिशन, गुवाहाटी के पास बीरुबारी श्मशान घाट में उसी दिन शाम लगभग 4:30 बजे उनके परिवार के सदस्यों, असम भाजपा के सचिव श्री फणींद्र नाथ सरमा और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कोविड मानदंडों के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार किया गया।

श्री देबदत्त बरकाताकी का जन्म 1 जनवरी, 1951 को गुवाहाटी में हुआ था। वह स्वर्गीय दुर्गादत्त बरकाताकी और बिली बरकाताकी के इकलौते पुत्र थे।

उन्होंने असमिया भाषा में ब्याबोहारिक रसायन (प्रैक्टिकल केमिस्ट्री), रसायन आदिपथ (रसायन विज्ञान की पहली किताब / गाइड), शिशु अरु आइना (बच्चा और दर्पण), गोलकीकरणर जन्मकोठा (वैश्वीकरण का इतिहास), मोटबिनिमॉय (संचार), सख्यारता ने स्वाख्यारता (साक्षरता पर) जैसी कई किताबें लिखीं। डावर आरे आरे— अंग्रेजी से असमिया भाषा में अनूदित पुस्तक उनकी आखिरी कृति थी, जिसे रानांगन प्रकाशन ने 2020 में प्रकाशित किया था।

वह 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा के आईटी संयोजक के रूप में अपना काम शुरू किया। उसके बाद उन्हें भाजपा पत्रिका और प्रकाशन विभाग के संयोजक के रूप में असोमिया बीजेपी बार्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई। पिछले 5 वर्षों से बरकाताकी ने लगभग अकेले ही बीजेपी बार्ता को हर महीने समय पर प्रकाशित करने

का काम किया।

ऐसे समर्पित पार्टी कार्यकर्ता का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है और कमल संदेश पत्रिका शोक संतप्त परिवार और उनके शुभिचंतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। ■

प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का किया उद्घाटन

आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो की लंबाई 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। यह 2014 में 9 किमी और 2017 में सिर्फ 18 किमी थी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो में यात्रा की। उन्होंने बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। पाइपलाइन का विस्तार मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर में पनकी तक है और पाइपलाइन से क्षेत्रवासियों को बीना रिफाइनरी के पेट्रोलियम उत्पादों तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री मोदी ने कानपुर के लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी और पाइपलाइन परियोजना के उद्घाटन के लिए बधाई दी। शहर के साथ अपने लंबे संपर्क को याद करते हुए उन्होंने कई स्थानीय संदर्भों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और कानपुर के लोगों के बेफ्रिक और अलग मिजाज का जिक्र भी किया।

उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और सुंदर सिंह भंडारी जैसे महान पुरुषों के व्यक्तित्व निर्माण में शहर की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा, "आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में जुटी है; हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं।"

श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य की छवि में हुए बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एक राज्य, जो अवैध हथियारों के लिए जाना जाता था, अब डिफेंस कॉरिडोर का हब है और देश की सुरक्षा व संरक्षा में योगदान दे रहा है। समय-सीमा का पालन करने की कार्य-संस्कृति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार उस काम को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करती है, जिसके लिए आधारशिला रखी गई है।

श्री मोदी ने कहा, "कानपुर मेट्रो का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है; पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया।" उन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश के समर्पित फ्रेट कॉरिडोर हब जैसी प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया, जो अभी निर्माण-प्रक्रिया में हैं।

> **एक राज्य, जो अवैध हथियारों के लिए जाना जाता था, अब डिफेंस कॉरिडोर का हब है और देश की सुरक्षा व संरक्षा में योगदान दे रहा है। समय-सीमा का पालन करने की कार्य-संस्कृति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार उस काम को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करती है, जिसके लिए आधारशिला रखी गई है**

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि साल 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में जितनी मेट्रो चलती थी, उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से लेकर 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। उन्होंने कहा कि अगर आज कानपुर मेट्रो को मिला दें, तो उत्तर प्रदेश में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की जरूरतों को समझते हुए दमदार काम कर रही है। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश के करोड़ों घरों में पहले पाइप से पानी नहीं पहुंचता था। आज हम हर घर जल मिशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने

में जुटे हैं।"

उन्होंने ट्रांसमिशन में सुधार, बिजली की स्थिति, शहरों और नदियों की सफाई का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए 2014 तक महज 2.5 लाख घरों की तुलना में पिछले साढ़े चार साल में 17 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। इसी तरह, सरकार का ध्यान पहली बार रेहड़ी-पटरी वालों की ओर गया और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से राज्य में 7 लाख से अधिक लोगों को 700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली। महामारी के दौरान सरकार ने राज्य में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की। साल 2014 में देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। अब 30 करोड़ से अधिक कनेक्शन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में ही 1.60 करोड़ परिवारों को नए एलपीजी कनेक्शन दिए गए।

श्री मोदी ने कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि योगी सरकार द्वारा माफिया संस्कृति को खत्म करने से उत्तर प्रदेश में निवेश में वृद्धि हुई है। व्यापार और उद्योग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक मेगा लेदर क्लस्टर कानपुर में और एक फजलगंज में मंजूर की है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं से कानपुर के उद्यमियों और व्यापारियों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के डर से अपराधी बैकफुट पर हैं। उन्होंने हाल ही में आधिकारिक छापेमारी के माध्यम से अवैध धन का पता लगाए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि जनता ऐसे लोगों की कार्य-संस्कृति को देख रही है। ■

बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना

356 किलोमीटर लंबी बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी तक फैली इस परियोजना को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह क्षेत्र में बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंचाने में मदद करेगी। ■

आईआईटी, कानपुर का 54वां दीक्षांत समारोह

प्रधानमंत्री ने लॉन्च की 'ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 दिसंबर को आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और संस्थान में विकसित ब्लॉकचेन-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की। संस्थान के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कानपुर के लिए एक महान दिवस है, क्योंकि शहर को मेट्रो की सुविधा मिल रही है और साथ ही उत्तीर्ण छात्रों के रूप में कानपुर दुनिया को बहुमूल्य तोहफा दे रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में भारत में 75 से अधिक यूनिकॉर्न, 50,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। इनमें से 10,000 स्टार्टअप तो पिछले 6 महीनों में ही शुरू हुए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। आईआईटी से निकले युवाओं ने कई स्टार्टअप शुरू किए हैं।

प्रधानमंत्री ने छात्रों को सलाह दी कि वे चुनौती के बजाय आराम को न चुनें। श्री मोदी ने कहा, "क्योंकि, आप चाहें या न चाहें, जीवन

में चुनौतियां आनी ही है। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं, लेकिन अगर आप चुनौतियों की तलाश में हैं, तो आप शिकारी हैं और चुनौती आपके लिए शिकार के समान है।" ■

उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा: नरेन्द्र मोदी

उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया, जिसके बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था और यह कई वर्षों से लंबित थी। उन्होंने 8,700 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये सड़क परियोजनाएं सुदूर, ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के विजन को साकार करेंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

उन्होंने ऊधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश उपग्रह केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। ये उपग्रह केंद्र देश के सभी हिस्सों में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप होंगे। उन्होंने काशीपुर में एरोमा पार्क और सितारगंज में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क और राज्य भर में आवास, स्वच्छता तथा पेयजल आपूर्ति में कई अन्य पहलों की आधारशिला रखी।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कुमाऊं के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया। उन्होंने उत्तराखंडी टोपी से सम्मानित करने के लिए क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने विस्तार से बताया कि वह क्यों सोचते हैं कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार धाम परियोजना, नए बन रहे रेल रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे।

उन्होंने पनबिजली, उद्योग, पर्यटन, प्राकृतिक कृषि और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड द्वारा की गई प्रगति के बारे में भी चर्चा की जो इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना देगी।

श्री मोदी ने पहाड़ी क्षेत्रों को विकास से दूर रखने की विचारधारा के बारे में कहा, "आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं देखी हैं। एक धारा है— पहाड़ को विकास से वंचित रखने की और दूसरी धारा है— पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर देने की।"

उन्होंने कहा कि विकास और सुविधाओं के अभाव में कई लोग क्षेत्र से अन्य स्थानों पर चले गए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश उपग्रह केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला राज्य में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।

उन्होंने कहा कि आज शुरू की जा रही परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि आज जो शिलान्यास किया जा रहा है वह संकल्प की आधारशिला है जिसे पूरे संकल्प के साथ पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अतीत की बदहाली और बाधाओं को अब सुविधाओं और सद्भाव में बदला जा रहा है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान हर घर जल, शौचालय, उज्ज्वला योजना, पीएमएवाई के माध्यम से महिलाओं के जीवन को नई सुविधाएं और सम्मान मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं में देरी करना पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। उन्होंने कहा, "आज यहां उत्तराखंड में जिस लखवाड़ परियोजना का काम शुरू हुआ है, उसका भी यही इतिहास है। इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। यह देरी किसी अपराध से कम नहीं है।"

श्री मोदी ने कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक हम एक मिशन में जुटे हैं। शौचालयों के निर्माण से, बेहतर सीवरेज सिस्टम से और पानी के ट्रीटमेंट की आधुनिक सुविधाओं से गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विकास की गति को तेज करना चाहता है। उन्होंने कहा, "आपके सपने, हमारे संकल्प हैं; आपकी इच्छा, हमारी प्रेरणा है; और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है।" श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का संकल्प इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना देगा। ■

प्रधानमंत्री ने मेरठ (उत्तर प्रदेश) में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी

भारतीय इतिहास में मेरठ संस्कृति और शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है: नरेन्द्र मोदी

खेल विश्वविद्यालय लगभग 700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा और इसमें 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता होगी

गत दो जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। खेल विश्वविद्यालय लगभग 700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा और सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल/वॉलीबॉल/हैंडबॉल/कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिमनैजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम सहित आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे से लैस होगा। इस विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता होगी।

एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरठ और आसपास के इस क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हों या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलख को इस क्षेत्र ने प्रज्ज्वलित रखा है।

श्री मोदी ने कहा, "भारतीय इतिहास में मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि संस्कृति और शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।" स्वतंत्रता संग्रहालय, अमर जवान ज्योति और बाबा औघर नाथ जी के मंदिर की भावना को महसूस करने पर प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी का इजहार किया।

श्री मोदी ने मेरठ में सक्रिय रहे मेजर ध्यानचंद को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यान चंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर किया था। उन्होंने कहा कि आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यान चंद जी को समर्पित की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य में लोकाचार में बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा कि पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फब्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे।

उन्होंने पहले के समय की असुरक्षा और अराजकता को याद किया। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। श्री मोदी ने कहा कि अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल-जेल खेल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा नए भारत का कर्णधार भी है, विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है, नेतृत्वकर्ता भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है और इसलिए जिधर युवा चलेगा उधर भारत चलेगा और जिधर भारत चलेगा उधर ही अब दुनिया चलने वाली है।

श्री मोदी ने कहा कि जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, उसमें भी खेल को प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स को अब उसी श्रेणी में रखा गया है, जैसे साईंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स स्कूल में बाकायदा एक विषय होगा।

मेरठ की खेल संस्कृति के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शहर 100 से अधिक देशों में खेल के सामान का निर्यात करता है। श्री मोदी ने उभरते खेल समूहों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह मेरठ न केवल 'लोकल फॉर वोकल' यानी स्थानीय के लिए मुखर है, बल्कि 'लोकल फॉर ग्लोबल' यानी स्थानीय को वैश्विक में बदल रहा है। ■

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' मेहनती किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करती है

विकास आनन्द

कृषि संकट के प्रभावी समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से कई योजनाओं की शुरुआत की और पिछली योजनाओं की कमजोरियों को दूर किया। उन योजनाओं और पहलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कृषक समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मेहनतकश किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है। नतीजतन, यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े कृषि में जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो रही है। आम तौर पर देखा गया है कि फसलें अचानक बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, अकारण बर्फबारी, बीमारी के हमले आदि से प्रभावित होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में पीएमएफबीवाई फसल के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री की 'फसल बीमा योजना' दुनिया में किसानों की भागीदारी के मामले में सबसे बड़ी बीमा योजना है और यह प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। मोदी सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ देना है। इस उद्देश्य के साथ सरकार किसानों के लिए देशभर में सबसे कम और एक समान प्रीमियम पर कृषि में जोखिम का व्यापक समाधान प्रदान करती है। इसे और अधिक समावेशी बनाते हुए इसके तहत बुवाई से पहले से लेकर फसल कटाई के बाद के नुकसान तक का जोखिम कवरेज प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने PMFBY के लिए 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह आवंटन बजट में पिछले आवंटन से 305 करोड़ अधिक था। बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से सरकार का इरादा अधिक से अधिक किसानों को बीमा का लाभ उपलब्ध कराने का है।

अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को दूर करके इस योजना का किसानों को आसानी से लाभ मिल सके इसके लिए मोदी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का योजना के क्रियान्वयन में उपयोग में लाया है। योजना के तहत किसान फसल नुकसान की सूचना फसल बीमा एप, कॉमन सर्विस सेंटर या नजदीकी कृषि अधिकारी के माध्यम से घटना के 72 घंटे के भीतर दे सकते हैं। क्लेम का लाभ पात्र किसानों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के जरिए प्रदान किया जाता है। पीएमएफबीवाई पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, किसानों के आसान नामांकन के लिए फसल बीमा मोबाइल ऐप, और फसल नुकसान का आकलन करने के लिए उपग्रह इमेजरी, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

निष्पादन और डेटाबेस बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) (www.pmfby.gov.in) को डिजाइन और विकसित किया है। बीमा पोर्टल ने किसानों, राज्यों, बीमाकर्ताओं और बैंकों के बीच बेहतर प्रशासन और समन्वय लाया है। साथ ही, साथ सूचना का वास्तविक समय पर प्रसार और कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। पोर्टल को 2018 में परिचालन में लाया गया था। पोर्टल के संचालन के बाद से राज्य सरकारें समन्वय के लिए एनसीआईपी(नेशनल क्रॉप बीमा पोर्टल)में स्थानांतरित हो गई है। सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सालाना आधार पर 5.5 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदन प्राप्त होते हैं।

2020 में योजना में सुधार करते हुए इस योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया था। जब इसे 2016 में शुरू किया गया था, तो यह गैर-स्वैच्छिक था। बैंकों से फसल ऋण लेने वालों के लिए यह अनिवार्य था। अब, उन किसानों के लिए यह अनिवार्य नहीं है जो कृषि ऋण का लाभ उठा रहे हैं। अब से यह योजना गैर-ऋणी किसानों और अन्य किसानों सहित सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है।

2021-22 में 16000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में 9719.24 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। 2021 में खरीफ सीजन के दौरान 244.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 484.6 लाख किसानों ने 99,368 करोड़ रुपये की बीमा राशि के लिए आवेदन दर्ज किया हैं। वर्ष 2020-21 में कुल आए 11,148 करोड़ रुपये के क्लेम के आवेदनों में से 110.7 लाख किसान को 10,385 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 29 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2016 से रबी सीजन 2020-21 तक कुल 29.16 करोड़ किसानों के आवेदन (68% ऋणी किसान का आवेदन और 32% गैर-ऋणी किसान आवेदन सहित) स्वीकृत किए गए हैं। सिर्फ 21 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम भुगतान पर इस योजना के तहत मुआवजे में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि आवंटित की गई है। इस योजना के प्रभावकारी होने के कारण किसानों का कृषि में रुचि बढ़ गयी है और वे नए-नए इनोवेशन और तकनीक का प्रयोग कृषि हेतु कर रहे हैं। ■

उजाला योजनाः आवश्यक बदलावों की ओर एक कदम

विपुल शर्मा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात साल पहले सभी के लिए सस्ती एलईडी योजना 'उजाला' का शुभारंभ किया, जो ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव डालने में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना को अब ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम में एक कहा जा रहा है और भारत में हजारों परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं जो न केवल उनके जीवन को बदल रही है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और विकास पथ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हाल ही में ग्लासगो में कॉप26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "उन देशों पर दबाव डालना समय की आवश्यकता है जो जलवायु को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को निभाने में विफल रहे हैं।" और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उजाला योजना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे 5 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसको लेकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया है। जिसमें अपने नागरिकों की ऊर्जा मांग को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास शामिल थे। इसके लिए सरकार ने एक ओर नवीकरणीय संसाधनों के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया, जबकि दूसरी ओर सरकार ने पुरानी शैली के तापदीप्त लैंप को ऊर्जा कुशल एलईडी बल्बों से बदलने का काम किया।

उजाला कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता की अवधारणा को बढ़ावा देने और क्रियान्वित करने में सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक लाइट बल्ब को एलईडी में बदलकर इस आंदोलन को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एलईडी बल्ब को 'प्रकाश पथ' यानी 'प्रकाश मार्ग' के रूप में वर्णित किया।

भारत में कुल ऊर्जा खपत में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है और एलईडी न केवल प्रकाश के स्तर में सुधार करते हैं बल्कि 50 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक ऊर्जा और लागत बचत को भी कम करते हैं। एक 7 वॉट की एलईडी न केवल 60 वॉट के तापदीप्त लैंप के समान ही रोशनी देता है, बल्कि यह बेहतर रोशनी प्रदान करता है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पिछले सात वर्षों में 36.78 करोड़ एलईडी लाइटें वितरित की हैं, जिससे प्रति वर्ष 47,778 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई है। बहुत ही कम समय में यह कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी शून्य-सब्सिडी घरेलू प्रकाश योजना के रूप में विकसित हुआ है जो उच्च विद्युतीकरण लागत और उच्च उत्सर्जन जैसी चिंताओं को दूर करता है।

इस कार्यक्रम की सफलता ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है, जो ऊर्जा दक्षता के लिए इसके अद्वितीय रणनीतिक दृष्टिकोण में निहित है। 'उजाला योजना' एलईडी बल्बों के खुदरा मूल्य जो 350 —300 रुपये प्रति बल्ब थी, उसे कम कर 70-80 रुपये प्रति बल्ब लाने में भी सफल रही। सस्ती ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ बनाने के अलावा, इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत भी हुई। इस योजना के बाद कार्बन उत्सर्जन में 3,86 करोड़ टन की कमी आयी और 9,565 मेगावाट की पीक डिमांड को रोका गया।

उजाला घरेलू उत्पादकों के लिए वरदान बन गई है, जो मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करती है। इस प्रयास से एलईडी बल्ब का घरेलू उत्पादन 1 लाख प्रति माह से बढ़कर 40 मिलियन प्रति माह हो गया है। उजाला के तहत नियमित थोक खरीद, अब इन निर्माताओं को नये अवसर भी प्रदान कर रही है। यह निर्माताओं को खुदरा क्षेत्र में बेचे जाने वाले एलईडी की लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। इससे खरीद लागत में लगभग 90 प्रतिशत की कमी देखी गयी है।

इस कार्यक्रम ने भारत के शीर्ष प्रबंधन स्कूलों का भी ध्यान आकर्षित किया है। यह अब आईआईएम, अहमदाबाद में लीडरशिप केस स्टडी का एक हिस्सा है। इसके अलावा, इसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

ग्राम उजाला योजना

जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने और बिजली बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च, 2021 में ग्राम उजाला की शुरुआत की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस कदम से प्रति वर्ष 2025 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी, जबकि कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 16.5 लाख टन की कमी आएगी। इस पहल के तहत, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पांच राज्यों के 2,579 गांवों में 10 रुपये की दर पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत स्थानीय निवासी अधिकतम 5 एलईडी बल्ब खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत पहले ही बिहार और उत्तर प्रदेश में 33 लाख से अधिक एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने का मुकाम हासिल कर लिया है। ■

कोरोना अभी गया नहीं है, सतर्कता सबसे महत्त्वपूर्ण है: नरेन्द्र मोदी

गत 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 3 जनवरी, 2022 से 15-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस कदम से स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने में मदद मिलने की संभावना है और इससे स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता की चिंता कम होगी।

उन्होंने 10 जनवरी, 2022 से स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए एहतियाती खुराक की भी घोषणा की। अग्रिम मोर्चे के कर्मी और स्वास्थ्य देखभाल कर्मी कोविड रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। भारत में तीसरी खुराक को बूस्टर डोज नहीं 'एहतियाती खुराक' कहा गया है। एहतियाती खुराक के निर्णय से स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का विश्वास मजबूत होगा। श्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि 10 जनवरी, 2022 से डॉक्टरों की सलाह पर सह-रुग्णता वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एहतियाती खुराक लेने का विकल्प उपलब्ध होगा।

भारत में ओमिक्रोन संक्रमण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को इससे नहीं घबराने की अपील की और मास्क पहनने तथा बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने कहा कि महामारी से लड़ने के वैश्विक अनुभव ने बताया है कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने का दूसरा हथियार टीकाकरण है।

श्री मोदी ने बताया कि इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान 141 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार कर चुका है। उन्होंने इस सफलता के लिए नागरिकों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के सामूहिक प्रयासों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि टीके की गंभीरता को बहुत पहले ही पहचान लिया गया था और टीके पर शोध के साथ-साथ अनुमोदन प्रक्रिया, आपूर्ति शृंखला, वितरण, प्रशिक्षण, आईटी सहायता प्रणाली और प्रमाणन पर काम किया गया। इन प्रयासों से देश की 61 प्रतिशत वयस्क आबादी को टीके की दोनों खुराक लग चुकी हैं और 90 प्रतिशत वयस्क आबादी को एक खुराक मिल चुकी है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज जैसे-जैसे वायरस के नए-नए रूप सामने आ रहे हैं, चुनौती का सामना करने की हमारी क्षमता और आत्मविश्वास भी हमारी अभिनव भावना के साथ कई गुना बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि आज देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1 लाख 40 हजार आईसीयू बेड, 90 हजार आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड विशेष रूप से बच्चों के लिए, 3 हजार से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। टीकाकरण और जांच तेज करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है।

श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि देश जल्द ही नेजल वैक्सीन और दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है।

श्री मोदी ने कहा कि 11 महीने का टीका अभियान देशवासियों के दैनिक जीवन में राहत लेकर आया है और सामान्य स्थिति को बहाल किया है। दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में आर्थिक गतिविधियां उत्साहजनक रही हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि कोरोना अभी गया नहीं है और सतर्कता सबसे महत्त्वपूर्ण है।

श्री मोदी ने अफवाह, भ्रम और भय फैलाने के प्रयासों के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने आने वाले दिनों में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को गति देने की अपील की। ■

प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण के 150 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल करने पर देशवासियों को दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जनवरी को कोविड टीके की 150 करोड़ खुराक लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन सभी लोगों का आभारी है, जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

सिलसिलेवार ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक दिन। 150 करोड़ टीके की खुराक देने की उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई। हमारे टीकाकरण अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। साथ ही साथ, हमें कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन भी करते रहना है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत उन सभी का आभारी है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और टीका लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को धन्यवाद देते हैं। मैं सभी पात्र लोगों से अपना टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। आइए, मिलकर कोविड-19 से लड़ें। ■

हमारी सामूहिक ताकत कोरोना वायरस को हराएगीः नरेन्द्र मोदी

भारत ने अपनी टीकाकरण मुहिम में 'अभूतपूर्व सफलता' हासिल की है, लेकिन वायरस के नए स्वरूप के कारण सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही, कोरोना वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत सतर्कता और अनुशासन देश की बड़ी ताकत है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 दिसंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 84वीं कड़ी में कहा कि भारत ने अपनी टीकाकरण मुहिम में 'अभूतपूर्व सफलता' हासिल की है, लेकिन वायरस के नए स्वरूप के कारण सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा, ''हमारे वैज्ञानिक इस नए ओमीक्रोन स्वरूप पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्हें हर रोज नए आंकड़े मिल रहे हैं और उनके सुझावों के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं।''

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत सतर्कता और अनुशासन देश की बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, ''हमारी सामूहिक ताकत कोरोना वायरस को हराएगी। हमें जिम्मेदारी की इस भावना के साथ 2022 में प्रवेश करना है।''

श्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी जिक्र किया, जिन्होंने तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हुए हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद पिछले सप्ताह बेंगलुरु के एक सैन्य अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 कर्मियों की मौत हो गई थी। आठ दिसंबर को हुए इस हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन सिंह ही जीवित बचे थे।

प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद उनके द्वारा अपने स्कूल को लिखे प्रेरणादायी पत्र का भी जिक्र दिया।

श्री मोदी ने 'मन की बात' में यह भी कहा कि किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देतीं, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ीं। अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड है, जिसे और बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हर नई शुरुआत अपने सामर्थ्य को पहचानने का भी एक अवसर लाती है। जिन लक्ष्यों की पहले हम कल्पना भी नहीं करते थे। आज देश उनके लिए प्रयास कर रहा है। हमारे यहां कहा गया है–

क्षणशः कणशश्चैव, विद्याम् अर्थं च साधयेत्।
क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम्।।

यानी, जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सीखना हो, करना हो, तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए और जब हमें, धन अर्जन करना हो, यानी उन्नति-प्रगति करनी हो तो हर एक कण का, यानी हर संसाधन का, समुचित इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि, क्षण के नष्ट होने से, विद्या और ज्ञान चला जाता है और कण के नष्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि ये बात हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है। हमें कितना कुछ सीखना है, नए-नए इन्नोवेशंस करने हैं, नए-नए लक्ष्य हासिल करने हैं। इसलिए, हमें एक क्षण गंवाए बिना लगना होगा। हमें देश को विकास की नयी ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से 'आत्मनिर्भर भारत' का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहरायें कि बड़ा सोचेंगें, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी-जान लगा देंगे और हमारे सपने केवल हम तक ही सीमित नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि हमारे सपने ऐसे होंगे जिनसे हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो, हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुलें और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक क्षण गवांए, बिना एक कण गवांये।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। ■

छह राज्यों को 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मिली मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित छह राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दे दी। यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे छह राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार एचएलसी ने एनडीआरएफ से 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जिसका विवरण निम्न है:

- चक्रवाती तूफान 'तौकते'-2021 के लिए गुजरात को 1,133.35 करोड़ रुपये;
- चक्रवाती तूफान 'यास'-2021 के लिए पश्चिम बंगाल को 586.59 करोड़ रुपये;
- दक्षिण पश्चिम मानसून, 2021 के दौरान बाढ़/भूस्खलन के लिए असम को 51.53 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 504.06 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 600.50 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 187.18 करोड़ रुपये।

यह अतिरिक्त सहायता केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में जारी की गई राशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ से 7 राज्यों को 3,543.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

चक्रवाती तूफान 'तौकते' और 'यास' के बाद एनडीआरएफ से गुजरात को 20.05.2021 को 1,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 29.05.2021 को 300 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से जारी किए गए थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के तुरंत बाद ही प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही 22 अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को वहां भेज दिया था। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

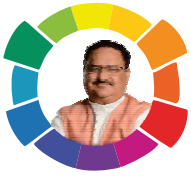

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

अगरतला (त्रिपुरा) में एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव व अन्य।

मणिपुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पारंपरिक स्वागत

कानपुर (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 10वीं किस्त जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मेरठ (उत्तर प्रदेश) में खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व अन्य नेतागण

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली स्थित उनकी समाधि 'सदैव अटल' पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह